Vishv UMIYA Foundation | VUF INSTITUTE CIVIL SERVICES

DAILY

CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 20-05-25

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Tuesday, 20 May, 2025

Edition : International

Table of Contents

Page 03 **Syllabus : Prelims Fact**	तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आदिवासी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सौर ऊर्जा योजना शुरू की
Page 06 **Syllabus : GS 2 : Governance and Social Justice**	रिपोर्ट से पता चलता है कि देरी से मिलने वाली मजदूरी मनरेगा कवरेज और डिलीवरी के बीच बेमेल का एक प्रमुख कारण है
Page 07 **Syllabus : GS 2 : International Relations**	डब्ल्यूएचओ ने अमेरिका के हटने के बाद जीवन की योजना बनाना शुरू किया
Page 09 **Syllabus : GS 2 : Governance and Social Justice**	किशोरों में मोटापे से निपटना
Page 10 **Syllabus : GS 2 : International Relations**	तुर्की और अजरबैजान के साथ भारत के संबंधों को समझना
Page 08 : Editorial Analysis: **Syllabus : GS 2 : Indian Polity**	पंचायत स्तर पर 'माइक्रोपिक्चर' प्राप्त करना

Page 03 : Prelims Fact

आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और सिंचाई की पहुंच में सुधार करने के लिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने नागरकुरनूल जिले में "इंदिरा सौरा गिरि जल विकासम" नामक एक नई योजना शुरू की। यह पहल सीधे आदिवासी कृषि संकट को संबोधित करती है और इसका उद्देश्य वंचित कृषि भूमि तक स्वच्छ ऊर्जा समाधान पहुंचाना है।

Telangana CM launches solar scheme to benefit tribal farmers

R. Ravikanth Reddy
HYDERABAD

Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy launched the 'Indira Saura Giri Jala Vikasam' scheme at Macharam in Nagarkurnool district on Monday and asked the officials to provide solar pumpsets to all the eligible Scheduled Tribes farmers in Achampet constituency within a month.

The Chief Minister, accompanied by Deputy Chief Minister Bhatti Vikramarka, said this was a unique scheme aimed at empowering the tribal farmers.

Mr. Reddy said the pilot project was being launched in Macharam for the benefit of tribals whose lands were allegedly snatched away during the BRS regime and cases were filed for protests. He suggested to the officials to involve the women's self-help groups in setting up solar power plants, so that they too could generate revenues from it.

CM Revanth Reddy during the launch of the scheme in Mahabubnagar on Monday. ANI

Under the Forest Rights Act, the government has sanctioned pattas for 6.69 lakh acres benefiting about 2.3 lakh farmers of Scheduled Tribes in the State. The new scheme aims to provide irrigation facilities using solar-powered borewells across six lakh acres of tribal land that don't have power connections.

Focussing on making women stronger financially, he said Telangana would see entrepreneurs among women due to government's initiatives like awarding works to generate 1000 MW of solar power to the women SHGs and also making them owners of buses.

Later, the Chief Minister went to his native village Kondareddypalle where he performed special poojas at the Anjaneya Swamy temple.

मुख्य विशेषताएँ:

- योजना का उद्देश्य: अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उन किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाली बोरवेल सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करना, जिनकी भूमि पर बिजली आधारित सिंचाई की सुविधा नहीं है।

- लक्ष्य समूह: अनुसूचित जनजाति के किसान, विशेष रूप से अचंपेट निर्वाचन क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में, जहाँ पिछली सरकार के दौरान भूमि कथित तौर पर खो गई थी या विकास से वंचित थी।
- पायलट स्थान: माचाराम गाँव, नागरकुरनूल जिला - योजना के प्रारंभिक कार्यान्वयन के लिए चुना गया।
- भूमि कवरेज और वन अधिकार अधिनियम: वन अधिकार अधिनियम के तहत, लगभग **2.3** लाख आदिवासी किसानों को **6.69** लाख एकड़ के पट्टे दिए गए हैं। नई सौर सिंचाई योजना का लक्ष्य लगभग **6** लाख एकड़ ऐसी भूमि है।
- महिला सशक्तिकरण एकीकरण: महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सौर संयंत्र स्थापित करने में शामिल किया जाना है। सरकार महिला एसएचजी के माध्यम से **1000** मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने और उन्हें बसों का स्वामित्व आवंटित करने की भी योजना बना रही है, जो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी की दिशा में एक मजबूत कदम है।
- राजनीतिक महत्व: इस कदम का उद्देश्य भूमि को बहाल करके और स्थायी सिंचाई सहायता प्रदान करके बीआरएस शासन के दौरान आदिवासी समुदायों के साथ हुए कथित अन्याय को दूर करना है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: हाल ही में तेलंगाना में शुरू की गई 'इंदिरा सौर गिरि जला विकासम' योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस योजना का उद्देश्य आदिवासी किसानों को सौर ऊर्जा चालित बोरवेल सिंचाई सुविधा प्रदान करना है।

2. इसे केंद्र सरकार की पीएम-कुसुम योजना के तहत लागू किया गया है।

3. इस योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को शामिल किया जाना है।

4. यह योजना वन अधिकार अधिनियम के तहत आवंटित भूमि को लक्षित करती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

a) केवल **1** और **3**

b) केवल **1, 3** और **4**

c) केवल **2** और **4**

d) 1, 2, 3 और **4**

उत्तर: b)

Page 06 : GS 2 : Governance and Social Justice

शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं के एक समूह लिबटेक इंडिया की एक हालिया रिपोर्ट ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के प्रदर्शन में बढ़ते अंतर का खुलासा किया है। जबकि इस योजना के तहत अधिक परिवारों के पंजीकरण के साथ कवरेज का विस्तार हुआ है, रोजगार के व्यक्ति-दिनों के संदर्भ में वास्तविक वितरण में गिरावट आई है, जो गहरी प्रणालीगत और कार्यान्वयन-स्तर की अक्षमताओं को उजागर करती है।

Report reveals delayed wages are a key factor to mismatch between MGNREGS coverage, delivery

Sobhana K. Nair
NEW DELHI

A review of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) for the financial year 2024-25 reveals that while the coverage has increased, with an 8.6% rise in number of registered households under the programme, the delivery of promised employment has gone down, with person days having dropped by 7.1%. This was revealed in a report released by LibTech India, a consortium of academics and activists on Monday.

Person days under the MGNREGS is defined as the total number of workdays by a person registered under the scheme in a financial year.

The LibTech study revealed that only 7% of households got 100 days of work. The MGNREG Act promises guaranteed employment up to 100 days. The report highlights that total registered households under the programme have gone up by 8.6% from 13.80 crore in FY 2023-24 to 14.98 crore in 2024-25. At the same time, average days of employment per household fell by 4.3%, from 52.42 person days in FY 2023-24 it went down to 50.18 person days in FY 2024-25. This, the LibTech report states, reflects a mismatch between the scheme's coverage and its delivery. "This trend raises questions about systemic and implementation-level challenges that continue to constrain the programme's effectiveness," the report said.

Women at work: Women levelling the land, under the MGNREGS, in ASR district of Andhra Pradesh. V. RAJU

Also, the persistent problem with the programme of regional variations continues. Odisha (34.8%) Tamil Nadu (25.1%) and Rajasthan (15.9%) saw the sharpest decline in person days, while Maharashtra (39.7%), Himachal Pradesh (14.8%), and Bihar (13.3%) recorded increases.

Inadequate allocation

Among the key factors leading to an overall employment drop are the inadequate allocation of budget and extraordinary delay in wage payments reported from across the country. Both issues have been highlighted on various platforms. The parliamentary Standing Committee on Rural Development in the past has raised concerns over reduction in budget allocation by the Union government and its effect on the progress of the scheme. People's Action for Employment Guarantee (PAEG) had recommended a budget allocation of ₹2.64 lakh crore for the MGNREGS for FY 2022-23 itself. However, the Union government has allocated only ₹86,000 crore for FY 2024-25. There was no revision in the MGNREGS budget for FY 2024-25.

The LibTech report also notes that the deletions of MGNREGS workers across the country have been arrested at least partially. Between 2022 and 2024, 7.8 crore workers were deleted.

The Ministry maintained that both deletions and additions are part of a regular process. But the rate of deletions far exceeded the rate of additions. In the corresponding period, only 1.92 crore workers were added. For the first time in FY 2024-25, this trend has been reversed, the report notes. So, while 99 lakh workers were deleted, 2.22 crore were added.

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- **कवरेज में वृद्धि लेकिन रोजगार वितरण में गिरावट:**
  - पंजीकृत परिवारों की संख्या में **8.6%** की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष **2023-24** में **13.80** करोड़ से बढ़कर **2024-25** में **14.98** करोड़ हो गई।

o इसके विपरीत, रोजगार के व्यक्ति-दिनों में **7.1%** की गिरावट आई, जो दर्शाता है कि योजना की बढ़ती मांग वास्तविक रोजगार सृजन के साथ मेल नहीं खा रही है।
o केवल **7%** परिवारों को अधिनियम के तहत मुख्य गारंटी के रूप में पूरे **100** दिन का रोजगार मिला।

- **औसत व्यक्ति-दिनों में गिरावट:**
  o पंजीकृत परिवारों की बढ़ती संख्या के बावजूद, प्रति परिवार औसत कार्यदिवस **52.42** से घटकर **50.18** हो गया।
  o यह कवरेज-वितरण बेमेल को दर्शाता है और योजना और निधि उपयोग की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है।

- **क्षेत्रीय असमानताएँ:**
  o जहाँ ओडिशा, तमिलनाडु और राजस्थान में रोजगार के दिनों में भारी गिरावट देखी गई, वहीं महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और बिहार में वृद्धि दर्ज की गई।
  o यह राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन में भिन्नता और संभवतः निधि जारी करने, शासन और स्थानीय माँग-आपूर्ति की गतिशीलता में अंतर को दर्शाता है।

- **विलंबित मज़दूरी और बजट बाधाएँ:**
  o विलंबित मज़दूरी भुगतान एक पुरानी समस्या बनी हुई है, जो विशेष रूप से सबसे ग़रीब लोगों के बीच भागीदारी को हतोत्साहित करती है।
  o बजटीय सहायता पूरी तरह से अपर्याप्त है - वित्त वर्ष **2024-25** के लिए **86,000** करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि **PAEG** जैसे नागरिक समाज समूहों द्वारा अनुशंसित **2.64** लाख करोड़ रुपये से बहुत कम है।
  o बढ़ती माँग के बावजूद बजट में कोई मध्य-वर्ष संशोधन नहीं होना नीतिगत जवाबदेही में उदासीनता को दर्शाता है।

- **कर्मचारियों की संख्या में कमी और वृद्धि:**
  o **2022** से **2024** तक, **7.8** करोड़ कर्मचारियों को हटाया गया, जबकि केवल **1.92** करोड़ को जोड़ा गया, जिससे पंजीकृत कार्यबल में महत्वपूर्ण शुद्ध घाटा हुआ।
  o हालाँकि, **2024-25** में पहली बार, प्रवृत्ति उलट गई - **99** लाख कर्मचारियों को हटाया गया जबकि **2.22** करोड़ को जोड़ा गया, जो संभावित रूप से कार्यान्वयन में सुधार का संकेत देता है।

व्यापक मुद्दे और निहितार्थ:

- प्रणालीगत शासन संबंधी मुद्दे: यह बेमेल खराब नियोजन, सक्रिय निधि जारी करने की कमी और प्रशासनिक बाधाओं को दर्शाता है, जो **100** दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी को कमजोर करता है।
- सामाजिक समानता संबंधी चिंताएँ: ग्रामीण आजीविका और लैंगिक सशक्तिकरण (विशेष रूप से महिला श्रमिकों के लिए) के लिए महत्वपूर्ण यह योजना वितरण में कमजोर पड़ रही है, जो ग्रामीण संकट और असमानता को बढ़ा सकती है।
- राजकोषीय मितव्ययिता बनाम कल्याणकारी दायित्व: कम बजट आवंटन सामाजिक सुरक्षा की कीमत पर राजकोषीय समेकन की ओर सरकार के व्यापक बदलाव को दर्शाता है।
- नीति-कार्यान्वयन वियोग: बढ़ते पंजीकरण के बावजूद घटते हुए व्यक्ति-दिवस क्षेत्र की वास्तविकताओं और नीति नियोजन के बीच वियोग को दर्शाते हैं।

आगे की राह:

- बजटीय सहायता में वृद्धि: केंद्र को मांग के आधार पर लचीले संशोधनों के साथ पर्याप्त और समय पर धन सुनिश्चित करना चाहिए।
- समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करना: विलंबित भुगतान के लिए वास्तविक समय की निगरानी और दंड तंत्र को एकीकृत करना।
- विकेंद्रीकृत योजना: अधिक उत्तरदायी कार्यान्वयन और मांग अनुमान के लिए स्थानीय ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना।
- सुरक्षा उपायों के साथ तकनीकी सुधार: पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें लेकिन उचित सत्यापन के बिना बड़े पैमाने पर विलोपन से बचें।
- जवाबदेही को मजबूत करना: नियमित ऑडिट, सामाजिक ऑडिट और शिकायत निवारण तंत्र को संस्थागत बनाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

- ग्रामीण भारत के लिए जीवन रेखा, विशेषकर आर्थिक संकट और जलवायु अनिश्चितताओं के समय में, मनरेगा को क्रियान्वयन में संकट का सामना करना पड़ रहा है। पर्याप्त वित्तपोषण, उत्तरदायी शासन और जमीनी स्तर की योजना के माध्यम से पात्रता और क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटना इसकी विश्वसनीयता और प्रभाव को बहाल करने के लिए आवश्यक है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS), **हालांकि कानूनी रूप से गारंटीकृत है, लेकिन कार्यान्वयन में लगातार कमी से ग्रस्त है। योजना के कवरेज और वितरण में हाल के रुझानों के प्रकाश में इस कथन की आलोचनात्मक जांच करें।**

Page : 07 : GS 2 : International Relations

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) वित्तीय और संरचनात्मक संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका सबसे बड़ा योगदानकर्ता (कुल निधि का लगभग 18%), पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के अधीन वापसी की प्रक्रिया शुरू कर चुका है।

A view of the World Health Organization headquarters in Geneva, Switzerland. REUTERS

WHO begins planning for life after the U.S. quits

Reuters

Hundreds of officials from the World Health Organization (WHO) will join donors and diplomats in Geneva from May 19 with one question dominating their thoughts: how to cope with crises from mpox to cholera without their main funder, the U.S..

The annual assembly, with its week of sessions, votes and policy decisions, usually showcases the scale of the U.N. agency set up to tackle disease outbreaks, approve vaccines, and support health systems worldwide.

This year, since U.S. President Donald Trump started the year-long process to leave the WHO with an executive order on his first day in office in January, the main theme is scaling down.

Just what that "high-value stuff" will be is up for discussion. Health officials have said the WHO's work in providing guidelines for countries on new vaccines and treatments for conditions from obesity to HIV will remain a priority.

One WHO slideshow for the event suggested work on approving new medicines and responding to outbreaks would be protected while training programmes and offices in wealthier countries could be closed.

The U.S. had provided around 18% of the WHO's funding. Its year-long exit process, mandated under U.S. law, means the U.S. will remain a WHO member until its official departure on January 21, 2026.

Trump – who accused the WHO of mishandling COVID, which it denies – muddied the waters days after his statement by saying he might consider

The U.S. provides around 18% of the WHO's funding. There is a mandated year-long exit process, which means the U.S. will remain a WHO member until its official departure on January 21, 2026

rejoining the agency if its staff "clean it up."

But global health envoys say there has since been little sign of a change of heart. So the WHO is planning for life with a $600 million hole in the budget for this year and cuts of 21% over the next two years.

As the U.S. prepares to exit, China is set to become the biggest provider of state fees, one of the WHO's main streams of funding alongside donations. Its contribution will rise from just over 15% to 20% of the total state fee pot under an overhaul of the funding system agreed in 2022.

Others have suggested this might be a time for an even broader overhaul rather than continuity under a reshuffled hierarchy of backers.

"Does WHO need all its committees? Does it need to be publishing thousands of publications each year?" Anil Soni, chief executive of the WHO Foundation, an independent fund-raising body for the agency, asked.

He said the changes had prompted a re-examination of the agency's operations, including whether it should be focused on details like purchasing petrol during emergencies.

Other business at the assembly includes the rubber-stamping a historic agreement on how to handle future pandemics and drumming up more cash from donors at an investment round.

But the focus will remain on funding under the new world order. In the run up to the event, a WHO manager sent an email to staff asking them to volunteer, without extra pay, as ushers.

- 21 जनवरी, 2026 को निर्धारित यू.एस. प्रस्थान से $600 मिलियन की फंडिंग की कमी होने की संभावना है और एजेंसी को अपनी प्राथमिकताओं और परिचालन मॉडल का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह विकास एमपॉक्स, हैजा और महामारी के बाद स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने सहित कई वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों के बीच हुआ है।

मुख्य मुद्दे और घटनाक्रम:

- **यू.एस. वापसी और बजटीय अंतर:**
  - o यू.एस. एक महत्वपूर्ण वित्तपोषक रहा है, जो डब्ल्यूएचओ के बजट का लगभग पाँचवाँ हिस्सा योगदान देता है।
  - o इसके बाहर निकलने से भारी मात्रा में वित्त पोषण घाटा पैदा होगा और विशेष रूप से वैश्विक निगरानी वैक्सीन दिशा-निर्देशों और प्रकोप प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की निरंतरता को खतरा होगा।
  - o डब्ल्यूएचओ अपनी आकस्मिक योजना के हिस्से के रूप में अगले दो वर्षों में 21% बजट कटौती की योजना बना रहा है।

- **पावर डायनेमिक्स में बदलाव:**
  - o अमेरिका के पीछे हटने के साथ, चीन शीर्ष राज्य योगदानकर्ता बनने के लिए तैयार है, जिसका हिस्सा 2022 के फंडिंग सुधार के तहत मूल्यांकन किए गए योगदान का 20% तक बढ़ जाएगा।
  - o यह संगठन के भीतर भू-राजनीतिक प्रभाव को नया रूप देता है, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य तटस्थता और संतुलन के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।

- **WHO की भूमिका और दक्षता का पुनर्मूल्यांकन:**
  - o संकट ने एजेंसी के मुख्य कार्यों और संसाधन उपयोग पर आंतरिक बहस को बढ़ावा दिया है।
  - o सुझावों में अमीर देशों में क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद करना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कम करना और व्यापक प्रकाशनों और समिति के काम में कटौती करना शामिल है।
  - o WHO से मुख्य जनादेशों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की माँग बढ़ रही है - बीमारी के प्रकोप, वैक्सीन विनियमन और स्वास्थ्य आपातकालीन तैयारियों पर प्रतिक्रिया करना।

- **संरचनात्मक सुधार और संस्थागत दक्षता:**
  o WHO फाउंडेशन, एक धन उगाहने वाली शाखा, ने परिचालन सुव्यवस्थित करने और नौकरशाही को कम करने की वकालत की है।
  o सवाल उठ रहे हैं: क्या WHO को आपात स्थितियों में ईंधन खरीद जैसे सूक्ष्म-स्तरीय लॉजिस्टिक्स में शामिल होना चाहिए? इस तरह के आत्मनिरीक्षण एजेंसी को संस्थागत सुधारों पर विचार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

- **महामारी संधि और आपातकालीन तैयारी:**
  o वित्तीय संकट के बीच, WHO असेंबली से एक ऐतिहासिक महामारी समझौते की पुष्टि करने की उम्मीद है, जो भविष्य की महामारियों के प्रबंधन के लिए नए वैश्विक नियम निर्धारित करेगा।
  o COVID-19 सबक के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण है, पारदर्शी डेटा साझाकरण, प्रारंभिक अलर्ट और टीकों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।

- **दाता निर्भरता और बहुपक्षीय कमज़ोरी:**
  o WHO की फंडिंग की दोहरी संरचना - मूल्यांकित योगदान (सदस्य राज्यों से) और स्वैच्छिक दान (राज्यों और निजी दाताओं से) - इसे राजनीतिक उतार-चढ़ाव और रणनीतिक वापसी के लिए असुरक्षित बनाती है।
  o बड़े दाताओं पर निर्भरता वैश्विक स्वास्थ्य समानता को कमजोर करती है, खासकर जब प्रमुख फंडर अपने स्वयं के स्वास्थ्य एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं।

- **मानव संसाधन और नैतिक संकट:**
  o वित्तीय संकट इस बिंदु पर पहुंच गया है कि डब्ल्यूएचओ के कर्मचारियों को जिनेवा असेंबली के दौरान बिना अतिरिक्त वेतन के स्वयंसेवक के रूप में काम करने के लिए कहा गया था, जो परिचालन तनाव की गहराई को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

- डब्ल्यूएचओ का मौजूदा संकट वैश्विक स्वास्थ्य शासन के भविष्य को फिर से परिभाषित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अमेरिका की वापसी न केवल वित्तीय स्थिरता बल्कि बहुपक्षीय वैधता और तटस्थता को भी खतरे में डालती है। चीन जैसे अन्य सरकारी वित्तपोषकों का उदय प्रभाव के संतुलन को बदल सकता है, जिससे संस्थागत सुरक्षा, फंडिंग तंत्र में सुधार और बढ़ी हुई पारदर्शिता की मांग हो सकती है। यह डब्ल्यूएचओ के लिए अपने मुख्य फोकस को खंडित दाता-नेतृत्व वाली प्राथमिकताओं से न्यायसंगत, जरूरतों पर आधारित वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई में बदलने का अवसर है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: विश्व स्वास्थ्य संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका का बाहर निकलना वैश्विक स्वास्थ्य बहुपक्षवाद में गहरे संकट का संकेत देता है। वैश्विक स्वास्थ्य शासन के भविष्य पर इस घटनाक्रम के प्रभावों की आलोचनात्मक जांच करें। (15 marks)

Page 09 : GS 2 : Governance and Social Justice

भारत में किशोरों में मोटापे को लेकर बढ़ती चिंता ने नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है, खास तौर पर पोषण पखवाड़ा के 7वें संस्करण के दौरान, जिसमें बच्चों के पोषण और मोटापे पर ध्यान केंद्रित किया गया। आईसीएमआर-एनआईएन, यूनिसेफ और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया सहित कई हितधारकों ने हाल ही में किशोरों के भोजन के माहौल को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सिफारिशें जारी की हैं।

- तीन महीने के भीतर पारदर्शी खाद्य लेबलिंग लागू करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश इस मुद्दे की तात्कालिकता को रेखांकित करता है। यह केवल स्वास्थ्य संबंधी चिंता नहीं है, बल्कि एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक और विकासात्मक चुनौती है।

Combating obesity among adolescents

Dr. SubbaRao M. Gavaravarapu

Scientist-F and Head, Nutrition Information, Communication and Health Education Division, ICMR-(National Institute of Nutrition NIN)

Dr. Bharati Kulkarni

Director, ICMR-NIN

There is an increased focus in public discourse on growing obesity among adolescents. The seventh edition of Poshan Pakhwada, held last month, focused on childhood and adolescent obesity alongside the first 1,000 days of life. The 'Let's Fix Our Food' consortium, a multi-stakeholder initiative spearheaded by the Indian Council of Medical Research-National Institute of Nutrition, the Public Health Foundation of India, UNICEF-India, and others, recently released a set of policy briefs advocating for the need to better the food environments for adolescents. Last month, in a move to improve transparency on food labels, the Supreme Court gave the Central government a strict three-month window to finalise and enforce transparent food labelling regulations. These measures point towards growing concern about the problem.

Nutrition paradox

Adolescence is a period of rapid growth and transformation that lays the foundation for future health and well-being. Yet, in India, this crucial stage is being compromised not only by the problem of under nutrition but also by an emerging epidemic of obesity and diet-related non-communicable diseases. Ironically, we now live in an era where reaching for a highly processed packaged food item is more convenient than choosing healthier alternatives. Poor nutrition, driven by the aggressive marketing and widespread availability of ultra-processed foods, is pushing our youth towards a lifetime burden of obesity, diabetes, and cardiovascular diseases. This is threatening their well-being and also the nation's long-term productivity and growth.

India has, for a while, been facing a nutrition paradox where under nutrition and obesity coexist. While malnutrition persists among children, obesity and diet-related diseases are surging at an alarming rate. As per the World Obesity Atlas 2024, India has one of the steepest annual increases in childhood obesity globally. The Comprehensive National Nutrition Survey indicates that on average, over 5% of adolescents in India and as many as 10-15% in about 10 States are either overweight or obese. For a country with a fifth of its population being adolescents, this is deeply concerning.

Adolescents are among the most vulnerable yet least empowered. In an apparently liberal food environment, their food choices appear to be many, but healthier options are not easy to find. Food choices are shaped by schools, social media, peer influence, and aggressive marketing. As highly processed foods, sugary drinks, and high sodium foods become dietary staples, obesity rates among teenagers continue to climb at an alarming pace. Nutrition, however, is not just a health issue – it directly impacts education, mental well-being, and future productivity. Poor nutrition is linked to decreased concentration, lower academic performance, and higher absenteeism, limiting students' potential. In our current food systems frameworks, a shift in power towards children (or those who uphold children's rights) is imminent to achieve healthy and equitable food systems that prioritise children's well-being. Government policies such as making nutrition a 'Jan Andolan (people's movement)', and school health and wellness programmes, will create greater awareness on nutrition.

Dealing with the crisis

What we essentially need is a two-pronged approach: strong regulatory policies that prioritise adolescent health and active youth engagement. How can policies ensure that healthy foods become accessible, affordable, and most importantly, aspirational in our diverse food environments? Fiscal measures such as a health tax on high fat, salt, and sugar, and subsidies for nutrient-rich foods, have proven to be somewhat effective in discouraging consumption of sugar sweetened beverages in other countries. We must implement front-of-pack nutrition labels to enable informed consumer choices, alongside stricter regulations to curb misleading advertisements targeting children, particularly on digital platforms and in schools.

Schools too play a critical role in shaping children's food environments. Nutrition education in schools and communities can empower the youth to make informed food choices, and take up physical activity. However, the problem is not only about a lack of awareness or bad food choices. There is a need to enhance food literacy as an essential life skill that can equip adolescents to differentiate between healthy and unhealthy food, whether they are bought from outside or prepared at home; help them choose diverse diets from what is locally grown; and to be able to read and decipher the information on food labels.

We also need inter-ministerial coordination. Nutrition falls under multiple ministries – Women and Child Development, Health, Agriculture, Industry, Consumer Affairs, and Education – and each is working on different aspects. However, without convergence in discourse and action, efforts remain fragmented. Initiatives such as Poshan Abhiyaan provide a framework for collaboration, but a united front from multiple sectors can advocate for stronger regulatory frameworks.

It is time to acknowledge that a healthier India demands more than awareness – it requires healthy eating plates, playgrounds, policy action, youth leadership, and a major shift in our food environments. When we prioritise healthy beginnings, we will pave the way for a hopeful future.

A healthier India demands more than awareness — it requires healthy eating plates, playgrounds, policy action, youth leadership, and a major shift in our food environments

कुपोषण का दोहरा बोझ:

- भारत पोषण विरोधाभास का सामना कर रहा है - कुपोषण और मोटापा एक साथ मौजूद हैं, खासकर किशोरों में। जबकि गरीब समुदायों के बच्चे बौनेपन और कमज़ोरी से जूझ रहे हैं, वहीं शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मोटापे और आहार से संबंधित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) में समानांतर वृद्धि देखी जा रही है।
- विश्व मोटापा एटलस **2024** के अनुसार, भारत बचपन में मोटापे की वार्षिक वृद्धि में सबसे ऊपर है।
- व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण से पता चलता है कि **5%** से अधिक किशोर अधिक वजन वाले या मोटे हैं, कुछ राज्यों में यह आंकड़ा **10-15%** तक बढ़ जाता है।

संरचनात्मक कारण और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव:

- अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ पारंपरिक, स्वस्थ विकल्पों की तुलना में अधिक सुलभ और सस्ते हैं।
- साथियों का दबाव, स्कूल कैफेटेरिया, सोशल मीडिया और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों का आक्रामक डिजिटल विपणन किशोरों की आहार संबंधी आदतों को आकार देता है।
- स्कूली पाठ्यक्रम में पोषण शिक्षा न्यूनतम है, और जीवन कौशल के रूप में खाद्य साक्षरता गायब है।
- किशोर, कमज़ोर होने के साथ-साथ प्रणालीगत और व्यावसायिक बाधाओं के कारण स्वस्थ विकल्प चुनने में भी सबसे कम सशक्त हैं।

खराब पोषण के परिणाम:

- खराब किशोर पोषण केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं है; यह प्रभावित करता है:
  - संज्ञानात्मक विकास: खराब एकाग्रता, कम शैक्षणिक प्रदर्शन।
  - मानसिक स्वास्थ्य: शरीर की छवि संबंधी समस्याओं और तनाव से जुड़ा हुआ है।
  - उत्पादकता: दीर्घकालिक आर्थिक क्षमता में कमी और स्वास्थ्य सेवा का बोझ बढ़ना।

नीतिगत उपाय और उनकी कमियाँ:

- पोषण अभियान, पोषण के लिए जन आंदोलन और स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम जैसी सरकारी पहल सकारात्मक कदम हैं।
- हालाँकि, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, उपभोक्ता मामले जैसे मंत्रालयों के बीच विखंडन के कारण अभिसरण की कमी होती है।
- किशोरों में मोटापे की समस्या को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय की आवश्यकता महत्वपूर्ण है।

क्या किया जाना चाहिए - एक दो-आयामी रणनीति:

1. **विनियामक और राजकोषीय हस्तक्षेप:**

- **o** उच्च वसा, चीनी और नमक (**HFSS)** खाद्य पदार्थों पर स्वास्थ्य कर और पौष्टिक खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी।
- **o** सूचित निर्णय लेने में सहायता के लिए पैक के सामने पोषण लेबलिंग।
- **o** अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना, विशेष रूप से डिजिटल मीडिया और स्कूल स्थानों के माध्यम से बच्चों को लक्षित करना।

2. **युवाओं को सशक्त बनाना और खाद्य प्रणालियों को बदलना:**

- **o** औपचारिक पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पोषण शिक्षा।
- **o** खाद्य साक्षरता: किशोरों को खाद्य लेबल पढ़ना, स्वस्थ/अस्वस्थ विकल्पों के बीच अंतर करना और स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों की सराहना करना सिखाना।
- **o** खेल के मैदान, पार्क और स्कूल-आधारित खेल कार्यक्रमों जैसी शारीरिक गतिविधि अवसंरचना।

निष्कर्ष:

- किशोरों में मोटापा केवल आहार संबंधी समस्या नहीं है, बल्कि खाद्य वातावरण, नीति विखंडन और वाणिज्यिक प्रभाव की प्रणालीगत विफलता है। स्वस्थ भारत के लिए जागरूकता से कहीं ज़्यादा की ज़रूरत है - इसके लिए बहु-क्षेत्रीय प्रतिक्रिया, मज़बूत विनियामक उपाय, सशक्त युवा नेतृत्व और टिकाऊ, न्यायसंगत खाद्य प्रणालियों की ज़रूरत है। आज किशोरों के पोषण में बदलाव करना कल भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश में निवेश है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत पोषण विरोधाभास का सामना कर रहा है, जहाँ किशोरों में कुपोषण और मोटापा दोनों एक साथ मौजूद हैं। भारत में किशोरों में बढ़ते मोटापे के लिए जिम्मेदार कारकों पर चर्चा करें। इस दोहरे बोझ को दूर करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप का सुझाव दें। (250 words)

Page 10 : GS 2 : International Relations

हाल की भू-राजनीतिक घटनाओं, खास तौर पर भारत में पहलगाम आतंकी हमले के बाद तुर्की और अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने से भारतीय नागरिक समाज, शिक्षा जगत और व्यापार जगत में तीखी प्रतिक्रिया हुई है।

- इन देशों का बहिष्कार करने, पर्यटन और शिक्षा संबंधों को रद्द करने और यहां तक कि अकादमिक सहयोग को निलंबित करने के लिए सार्वजनिक आह्वान किया गया है। इसने भारत की विदेश नीति के रुख पर एक महत्वपूर्ण बहस को फिर से शुरू कर दिया है, खासकर उन देशों के प्रति जो ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।

Understanding India's relationship with Turkey and Azerbaijan

Data suggests that even if an official trade ban is issued against these two nations, India stands to lose little

DATA POINT

Nitika Francis
Sambavi Parthasarathy
Vignesh Radhakrishnan

Following Turkiye and Azerbaijan's support for Pakistan after India's military confrontation in the wake of the Pahalgam massacre, many online travel platforms reported a sharp spike in cancellations of tour bookings to these countries. Many Indian tour operators withdrew offers and promotional packages for trips to Turkiye and Azerbaijan. On social media, calls to "boycott" both countries gained traction. Institutions such as IIT Bombay, IIT Roorkee, and Jawaharlal Nehru University suspended MoUs with some Turkish universities.

Data show that the relationship between Pakistan and Turkiye has been strengthened by arms trade. The two countries have also shown reciprocal support during past geopolitical standoffs. For instance, Turkiye has backed Pakistan on the Kashmir issue, while Pakistan has supported Turkiye in disputes related to Cyprus.

Similarly, in 2020, it was with Turkish backing that Azerbaijan captured much of the Armenian-populated enclave from Armenia. Though Azerbaijan regained full control of the region in 2023, Turkiye denied any direct involvement in that year's operation.

Data from the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) shows that Turkiye has been exporting arms to Pakistan since the 1990s. **Chart 1** shows Turkiye's arms exports to Pakistan between 1995 and 2023 by category and volume. A significant share of this trade comprised artillery – defined as naval, fixed, self-propelled guns, howitzers, and multiple rocket launchers. Pakistan also received armoured vehicles from Turkiye, including tanks, armoured cars, and personnel carriers.

India has supplied weapons to Armenia **(Chart 2)**. Most of these exports comprise surface-to-air missile systems and a few multiple rocket launchers. In contrast, SIPRI data shows no official arms transactions between India and Azerbaijan, or India and Turkiye.

Last week, some Indian trader associations passed resolutions to boycott all forms of trade and commercial engagement with Turkiye and Azerbaijan. However, data suggests that even if this escalates into an official trade ban, India stands to lose little. Crude oil is the primary import from both countries, but their combined share in India's total crude imports has remained below 1% over the past six years **(Chart 3)**. In contrast, Azerbaijan could face a greater impact, as India was its third largest destination for crude oil as of 2023.

Another major import from Turkiye is machinery and mechanical appliances, including nuclear reactors, boilers, and related parts. But even in this category, Turkiye accounts for only about 1% of India's total imports **(Chart 4)**. India remains far more dependent on countries such as China and Germany for such equipment.

While calls to boycott Turkiye and Azerbaijan have led to "mass cancellations" of travel bookings from India, data shows that Indian tourists formed less than 1% of all tourists to Turkiye in 2024. That said, the number of Indian visitors to Turkiye has been rising steadily in recent years **(Chart 5)**.

In 2023, Indians made up less than 6% of all tourists in Azerbaijan, but this share rose to around 10% in 2024. The boycott calls, therefore, come at a time when Indian travel to both these countries was on the rise **(Chart 6)**.

The number of Indian students pursuing higher education in Turkey and Azerbaijan has also increased in recent years. In 2017, the number of Indian students in these countries was less than 100. As of January 2024, it increased by at least seven times (777).

Interests in **conflict**

The data for the charts were sourced from SIPRI, the Lok Sabha, Turkey's Ministry of Culture and Tourism, the Azerbaijan Tourism Board, UN Comtrade, the Ministry of Commerce, and the Azerbaijan State Statistical Committee

Chart 1: The chart shows Türkiye's arms exports to Pakistan between 1995 and 2023

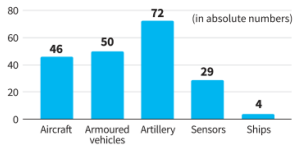

Chart 2: The chart shows India's weapons exports to Armenia over the years

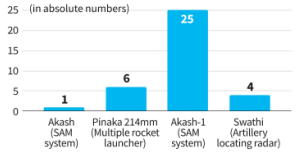

Chart 3: The country-wise share of India's imports of crude oil over the six years

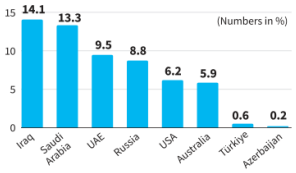

Chart 4: The country-wise share of India's imports of nuclear reactors and machinery

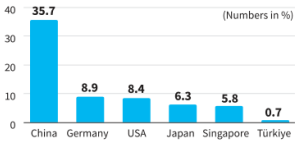

Chart 5: The chart shows the number of tourists from India and Pakistan to Türkiye

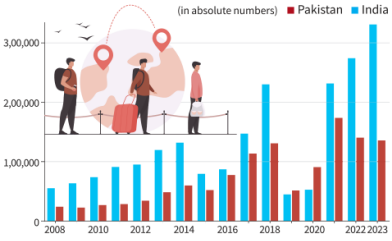

Chart 6: The chart shows the number of tourists from India and Pakistan to Azerbaijan

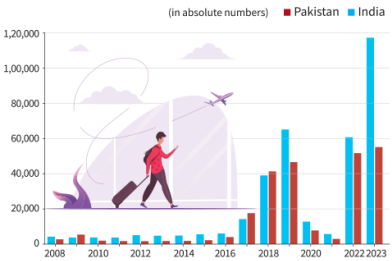

भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि:

- **तुर्की-पाकिस्तान गठजोड़:**
  o तुर्की ने लंबे समय से कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया है, जिसके जवाब में साइप्रस पर पाकिस्तान ने तुर्की का समर्थन किया है। उनकी साझेदारी सैन्य रूप से भी मजबूत है, तुर्की **1990** के दशक से लगातार पाकिस्तान को तोपखाने और बख्तरबंद वाहनों जैसे हथियार निर्यात कर रहा है।

- **अज़रबैजान-तुर्की गठबंधन:**
  o आर्मेनिया के साथ नागोर्नो-करबाख संघर्ष में अज़रबैजान की सैन्य सफलता को व्यापक रूप से तुर्की द्वारा समर्थित माना जाता था, हालाँकि अंकारा ने आधिकारिक तौर पर प्रत्यक्ष भागीदारी से इनकार किया था। इसके विपरीत, भारत ने मिसाइल सिस्टम और रॉकेट लॉन्चर सहित आर्मेनिया को सैन्य सहायता प्रदान की है, जिससे भारत और अज़रबैजान के बीच रणनीतिक मतभेद पैदा हुए हैं।

भारत की रणनीतिक स्थिति:

- जबकि भारत और तुर्की/अज़रबैजान के बीच कोई आधिकारिक हथियार व्यापार नहीं है, भारत ने तुर्की के क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी आर्मेनिया के साथ संबंध विकसित किए हैं, जो दक्षिण काकेशस में एक सूक्ष्म संतुलन रणनीति का संकेत देता है।
- आर्मेनिया के साथ भारत की बढ़ती सैन्य भागीदारी इस्लामी दुनिया में तुर्की के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने और पाकिस्तान के रणनीतिक स्थान को सीमित करने के अपने व्यापक भू-राजनीतिक लक्ष्यों के साथ संरेखित है।

व्यापार और आर्थिक आयाम:

- **मीडिया में हंगामे के बावजूद, आर्थिक संबंध सीमित हैं:**
  o तुर्की और अज़रबैजान से कच्चे तेल का संयुक्त आयात भारत के कुल कच्चे तेल आयात का **1%** से भी कम है।
  o तुर्की से मशीनरी और यांत्रिक उपकरण भी भारत के आयात टोकरी का लगभग **1%** हिस्सा हैं।

- **पर्यटन और शिक्षा प्रभाव:**
  o भारतीय पर्यटक तुर्की के कुल पर्यटक प्रवाह का **1%** से भी कम हिस्सा हैं, हालांकि बहिष्कार से पहले संख्या बढ़ रही थी।
  o इसी तरह, अज़रबैजान में, **2024** में सभी पर्यटकों में भारतीयों की संख्या लगभग **10%** होगी।
  o दोनों देशों में भारतीय छात्रों की संख्या, हालांकि बढ़ रही है (**2024** तक **777**), यू.एस., यू.के. या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।

भारतीय विदेश नीति के लिए निहितार्थ:

- कम व्यापार जोखिम, उच्च प्रतीकात्मकता: तुर्की और अज़रबैजान के लिए भारत का आर्थिक जोखिम न्यूनतम है, जिसका अर्थ है कि राजनयिक या वाणिज्यिक बहिष्कार भारत के हितों को गंभीर रूप से नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन अस्वीकृति का एक प्रतीकात्मक संदेश भेजेगा।
- पाकिस्तान को रणनीतिक संकेत: विश्वविद्यालय समझौता ज्ञापनों और पर्यटन जुड़ाव को निलंबित करके भारत ने विशेष रूप से आतंकवादी घटनाओं के बाद कूटनीतिक या सैन्य रूप से पाकिस्तान का समर्थन करने वाले राज्यों के प्रति शून्य-सहिष्णुता के दृष्टिकोण को रेखांकित किया है।
- बढ़ता वैश्विक संतुलन: आर्मेनिया के लिए भारत की पहुँच एक वास्तविक राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो तुर्की-अज़रबैजान-पाकिस्तान त्रिपक्षीय गतिशीलता को एक प्रति-त्रिपक्षीय संरेखण (भारत-आर्मेनिया-ग्रीस/साइप्रस) के साथ संतुलित करती है।
- कूटनीतिक विवेक की आवश्यकता: जबकि लोकप्रिय भावना शत्रुतापूर्ण राज्यों को अलग-थलग करने के पक्ष में है, विदेश नीति को दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, खासकर जब भारत मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहा है।

निष्कर्ष:

- तुर्की और अज़रबैजान के साथ भारत के संबंध, आर्थिक दृष्टि से सतही होने के बावजूद, गहरी रणनीतिक और वैचारिक चुनौतियों को दर्शाते हैं। तुर्की का पाकिस्तान को खुला समर्थन, इस्लामी दुनिया का नेतृत्व करने की उसकी महत्वाकांक्षा और उसकी क्षेत्रीय सक्रियता भारत के लिए कूटनीतिक और सुरक्षा संबंधी दोनों तरह की चिंताएँ पैदा करती हैं। हालाँकि भारत को संबंधों में दरार से कोई खास नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन पश्चिम और मध्य एशिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को बनाए रखने के लिए कूटनीतिक जुड़ाव के साथ रणनीतिक प्रतिरोध को मिलाकर एक संतुलित रणनीति बनाना ज़रूरी है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: तुर्की और अज़रबैजान के साथ भारत के भू-राजनीतिक तनाव पश्चिम और मध्य एशिया में गहरे रणनीतिक गठबंधन को दर्शाते हैं। तुर्की और अज़रबैजान के पाकिस्तान के साथ बढ़ते संबंधों के भारत की क्षेत्रीय कूटनीति पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा करें। (250 words)

Page : 08 Editorial Analysis

Getting the 'micropicture' at the panchayat level

Evidence-based decision-making has been the buzzword for the government for quite some time now. However, the extent of data-based decision-making in practice remains an open question.

Critics point to the delay in conducting Census operations and releasing Census data to researchers. They also highlight the other surveys carried out by the government and/or the change in methodology, thereby making the availability of time series data difficult, as obstacles to overcome in evidence-based decision-making at all levels of government. But government officials point to the availability of mammoth data in the portals of different Ministries and also the National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP), 2012 of the Government of India. This policy intended to make non-sensitive government data available to the public in an open, accessible, and reusable format (https://data.gov.in).

However, researchers complain that the data made available are not in a format which can be easily understood by the public or elected representatives. Citizens and even trained researchers feel overwhelmed by the voluminous data. Data visualisation tools on https://data.gov.in as well as other government portals are relatively under-developed. Data analytics leaves a lot to be desired. Consequently, decisions continue to be made based on experience and/or the intuitions of Ministers and senior bureaucrats at the Union and State levels.

Data generation and use

At the grassroots level – the gram panchayats, blocks and districts – data are only generated and fed into the system for use by senior officials at the State and national headquarters. Generally, portals are designed to meet the requirements of the heads of departments and secretaries and certainly not of government functionaries and elected representatives at the district, block or gram panchayat levels. Thus, we always get the 'mega picture' and not the 'micro picture'. Data at the gram panchayat level gets linked to a household and family and so becomes difficult to ignore if presented in an easily understandable form to residents.

Sunil Kumar

is a visiting faculty at the Gokhale Institute of Politics and Economics and a member of the Pune International Centre. He is also a former Secretary of the Ministry of Panchayati Raj, Government of India

The PAI portal can become a useful tool for officials of line departments and help local and State governments

On the PAI

It is in this context that the magnitude of the work that has gone into the making of Panchayat Advancement Index (PAI) Baseline Report 2022-23 (officially released in April 2025 by the Ministry of Panchayati Raj) needs to be understood. PAI is a composite Index and has been compiled based on 435 unique local Indicators (331 mandatory and 104 optional) with 566 unique data points across nine themes of LSDGs (Localization of Sustainable Development Goals) aligned with the National Indicator Framework (NIF) of the Ministry of Statistics and Programme Implementation. Validated data relating to over 2.16 lakh gram panchayats have been analysed and presented in a form where even a sarpanch or ward member can understand (with some support) not only where their GP stands in relation to the nine LSDGs but also what needs to be done to achieve them. Data relating to a little over 11,000 GPs were not included in PAI as they could not be validated as in laid down procedure. While 25 States/Union Territories provided validated data of almost 100%GPs, it is a matter of serious concern that Uttar Pradesh provided data for only 23,207 GPs (40%) out of its 57,702 GPs. This omission raises serious questions about the state of development in U.P. The PAI portal (www.pai.gov.in) can serve as a useful tool for officials of line departments. A constituency-wise report generation facility can prove very useful for even Members of Parliament and Members of the Legislative Assembly if they wish to make a specific intervention in respect of any LSDG.

It is a dramatic shift that data have now been linked to outcome. For instance, is the GP really a healthy panchayat? Based on the scores of GP on Healthy Panchayat indicators, gaps can now be easily identified and plugged in a short period. Further, the role of all stakeholders such as the individual, community, elected representatives and frontline workers of the health department would also suggest themselves. Excellent coordination between the frontline workers of development departments such as rural development, panchayati raj, education, health, drinking water and elected panchayat representatives and civil society organisations (CSOs) is seen as a very important factor in the performance of GPs on PAI.

It would be ideal if over 4,000 institutions linked with the Unnat Bharat Abhiyan undertake a study of at least five gram panchayats in their vicinity and explain to the community the implications of their PAI score and what could be done by them to improve their score. Hand-holding of GPs by these institutions and CSOs would go a long way in supplementing the role of departmental officials and attaining the SDGs. The PAI score card also has implications for how corporate social responsibility funds, the Prime Minister's Mineral Area Fund administered by the District Mineral Foundation (DMF), Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) and Member of Legislative Assembly Local Area Development Scheme (MLALAD) among others can be used for realisation of SDGs by 2030.

Need for analysts

There is an urgent need to provide trained data analysts at the block and district panchayat levels who can prepare and provide regular report cards for various stakeholders. More than the Union Government, PAI can be a gamechanger for State and local governments. A Similar Achievement Index should also be formulated for urban local governments. A baseline PAI report should be followed by publications of reports at regular intervals especially after the difficult groundwork has been done.

PAI is much more than a ranking of GPs, Districts or States. It is a call for action. GPs faring poorly are in need of support. We need to not only understand where funds are going or how they are being used (or misused). We need to use the latest data visualisation tools to make all stakeholders understand their critical role and ensure that the goal of making India march forward on the path of development becomes a reality.

The views expressed are personal

Paper 02 : भारतीय राजनीति

UPSC Mains Practice Question : साक्ष्य-आधारित शासन की शुरुआत जमीनी स्तर से होनी चाहिए। पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) और भारत में स्थानीय स्वशासन को बेहतर बनाने में इसकी भूमिका के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा करें। (250 words)

संदर्भ:

- शासन में साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने पर जोर भारत में बढ़ रहा है, लेकिन डेटा को कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि में बदलना, विशेष रूप से जमीनी स्तर पर, सीमित है।
- पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 का शुभारंभ ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर विकासात्मक परिणामों के साथ डेटा को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- पीएआई को निर्वाचित प्रतिनिधियों और नागरिकों को यह समझने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि उनकी पंचायत प्रमुख विकासात्मक मापदंडों पर कहाँ खड़ी है और सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण को प्राप्त करने के लिए किन हस्तक्षेपों की आवश्यकता है।

डेटा-संचालित शासन में चुनौतियाँ:

- **डेटा उपलब्धता और उपयोगिता के बीच अंतर:**
  o हालाँकि data.gov.in जैसे प्लेटफ़ॉर्म राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और पहुँच नीति (NDSAP), 2012 के तहत विशाल सरकारी डेटासेट होस्ट करते हैं, लेकिन इस डेटा की प्रस्तुति, विज़ुअलाइज़ेशन और व्याख्या अपर्याप्त है।
  o प्रशिक्षित शोधकर्ताओं, निर्वाचित जमीनी स्तर के प्रतिनिधियों की तो बात ही छोड़िए, अक्सर खराब डिजाइन, अत्यधिक तकनीकीता या डेटा की मात्रा के कारण सार्थक अंतर्दृष्टि निकालने में कठिनाई महसूस करते हैं।

- **डेटा सिस्टम का टॉप-डाउन ओरिएंटेशन:**
  o अधिकांश मौजूदा डेटा पोर्टल और एमआईएस प्लेटफ़ॉर्म स्थानीय हितधारकों जैसे सरपंचों, वार्ड सदस्यों या फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने के बजाय केंद्रीय या राज्य-स्तरीय निगरानी के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
  o परिणामस्वरूप, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों के लिए "मैक्रो पिक्चर" उपलब्ध है, जीपी स्तर पर "माइक्रो पिक्चर" धुंधली बनी हुई है।

पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) का महत्व:

- एसडीजी और राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ संरेखित नौ विषयगत क्षेत्रों में 435 स्थानीय संकेतकों का उपयोग करके विकसित समग्र सूचकांक।
- कवरेज: 2.16 लाख से अधिक जीपी के डेटा को स्थानीय प्रतिनिधियों के लिए भी समझने योग्य बनाया गया है।
- परिणाम-उन्मुख: उदाहरण के लिए, यदि कोई GP "स्वस्थ पंचायत" पर खराब स्कोर करता है, तो हितधारक सटीक अंतरालों की पहचान कर सकते हैं - जैसे टीकाकरण, स्वच्छता, या कुपोषण - और सुधारात्मक कार्रवाई की योजना बना सकते हैं।
- जवाबदेही और पारदर्शिता: निर्वाचन क्षेत्र-वार रिपोर्ट तैयार करने से सांसदों, विधायकों और नागरिक समाज संगठनों को स्थानीय विकास अंतरालों को ट्रैक करने और उनका जवाब देने की अनुमति मिलती है।

कार्यान्वयन अंतराल और राज्य-स्तरीय मुद्दे:

- उत्तर प्रदेश की कम रिपोर्टिंग (केवल 40% GP) राज्य स्तर पर डेटा की गुणवत्ता और राजनीतिक इच्छाशक्ति के बारे में चिंता पैदा करती है।
- कुछ GP (11,000+) को डेटा को मान्य करने में विफलता के कारण बाहर रखा गया था - जो बेहतर प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और समर्थन तंत्र की आवश्यकता की ओर इशारा करता है।

सिफारिशें और आगे का रास्ता:

- क्षमता निर्माण और जमीनी स्तर पर डेटा साक्षरता: PAI-आधारित रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रशिक्षित डेटा विश्लेषकों की तैनाती।
  o स्थानीय समुदायों के लिए पीएआई स्कोर की व्याख्या करने में शैक्षणिक संस्थानों (जैसे उन्नत भारत अभियान के तहत) को शामिल करें।
- नागरिक सहभागिता और जवाबदेही: सीएसओ और विश्वविद्यालयों को नागरिकों को पीएआई स्कोर समझाने में मदद करनी चाहिए और समुदाय के नेतृत्व वाली योजना और सामाजिक लेखा परीक्षा को बढ़ावा देना चाहिए।
- विकास निधि के साथ एकीकरण: पीएआई एसडीजी संकेतकों में अंतर को भरने के लिए कम प्रदर्शन करने वाले जीपी को सीएसआर फंड, डीएमएफ, एमपीएलएडी/एमएलएएलएडी के लक्षित आवंटन का मार्गदर्शन कर सकता है।
- शहरी विस्तार की आवश्यकता: शहरी विकास लक्ष्यों पर प्रगति को ट्रैक करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए एक समान उपलब्धि सूचकांक तैयार किया जाना चाहिए।
- डेटा विज़ुअलाइज़ेशन टूल और रियल-टाइम डैशबोर्ड: पीएआई को अधिकारियों और नागरिकों दोनों के लिए अधिक इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक डेटा विज़ुअलाइज़ेशन इंटरफेस विकसित किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष:

- पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) स्थानीय शासन में इनपुट-आधारित निगरानी से परिणाम-आधारित योजना में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह केवल रैंकिंग टूल नहीं है, बल्कि विकेंद्रीकृत नियोजन, पारदर्शिता और सहभागितापूर्ण शासन के लिए एक रणनीतिक साधन है। भारत को 2030 तक एसडीजी को सही मायने में हासिल करने के लिए, एक समय में एक पंचायत के विकास के'सूक्ष्म चित्र' पर आधारित प्रयास करने होंगे।